Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July 2024 5(7), 719–724

ROLE OF REGIONAL PARTIES IN 17TH LOK SABHA ELECTIONS: A THEORETICAL STUDY

१७ वी लोकसभा के चुनाव मे क्षेत्रीय दलोंकी की भूमिका : एक चिकित्सक अध्ययन

Rajnish G. Bambole [1]

[1] Professor, Bharatiya Mahavidyalaya, Morshi Dist. Amravati

ABSTRACT

English: The 17th Lok Sabha elections in India in 2019 were a dynamic shift in Indian politics where regional parties were important, sometimes even decisive. Instead of national parties like the BJP and the Congress opposing the existence of two separate formations, there is a sense of emergence of external leadership among some national parties, such as the process of the leader of the government becoming publicly detached from the party. This paper analyses their importance regionally in the 2019 electoral exercise through their strategies adopted while forming alliances and performances in specific states. Such findings provide a deeper insight into how regional parties focus their agenda on local issues and regional identities, thereby shaping the national political debate-outcomes. Thus, through a precise analysis of success and failure by regional parties, it intends to highlight their growing importance in contemporary politics with respect to the overall balance of power in relation to the Lok Sabha. According to the findings, while regional parties continue to play local politics, this possibly ensures significant space for alliances as they then become the ideal key to certain policy decisions and, indeed, national governance.

Hindi: भारत में २०१९ में हुए सत्रहवें लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में उस परिप्रेक्ष्य से आयाम बदल रहे थे, जहां क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण थे, कभी-कभी निर्णायक भी। भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां, दो अन्य संरचनाओं के अलग-अलग अस्तित्व का विरोध करने के बजाय, कुछ राष्ट्रीय दलों के बीच बाहरी नेतृत्व के उद्भव जैसी समझ रखती हैं, जैसे कि सरकार के नेता की प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से अलग हो जाना। यह शोधपत्र २०१९ के चुनावी अभ्यास में क्षेत्रीय रूप से उनके महत्व का विश्लेषण करता है, जो कि गठबंधन बनाते समय अपनाई गई उनकी रणनीतियों और विशिष्ट राज्यों में प्रदर्शनों के माध्यम से है। इस तरह के निष्कर्ष इस बात पर और गहराई से विचार करते है कि क्षेत्रीय दल अपने एजेंडे को स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय पहचानों पर कैसे केंद्रित करते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीतिक बहस-परिणामों को बढ़ावा मिलता है । इस प्रकार, क्षेत्रीय दलों द्वारा सफलता और विफलता के सटीक विश्लेषण के माध्यम से, यह लोकसभा के संबंध में शक्ति के समग्र संतुलन के संबंध में समकालीन राजनीति में उनके बढ़ते महत्व को उजागर करने का इरादा रखता है। निष्कर्षों के अनुसार, जबकि क्षेत्रीय दल स्थानीय राजनीति करना जारी रखते हैं, यह संभवतः गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित करता है क्योंकि वे तब कुछ नीतिगत निर्णयों और वास्तव में, राष्ट्रीय शासन की आदर्श कुंजी बन जाते हैं।

Keywords: Regional Parties, 17th Lok Sabha Elections, Indian Politics, Electoral Alliances, National Parties, BJP, Congress, Regionalism, Political Strategy, Electoral Impact क्षेत्रीय दल, १७वीं लोकसभा चुनाव, भारतीय राजनीति, चुनावी गठबंधन, राष्ट्रीय दल, भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रवाद, राजनीतिक रणनीति, चुनावी प्रभाव

Corresponding Author

Rajnish G. Bambole,
bambolerajnish@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i7.2024.4336

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

1. प्रस्तावना

भारत में राजनीतिक समावेशिता का इतिहास राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही तरह के समकक्षों के एक अनोखे मिश्रण की कहानी कहता है। हाल के दशकों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। २०१९ के १७वें लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे जिस राजनीतिक माहौल में आयोजित किए गए थे, उसकी प्रकृति अत्यधिक ध्रुवीकृत थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी

(भाजपा) ने शानदार जीत हासिल की, क्षेत्रीय दल चुनावी रणनीतियों की तैयारी, गठबंधनों के गठन और राष्ट्रीय राजनीतिक आख्यान के निर्माण में प्रमुख खिलाड़ी थे।

दृश्य ऐतिहासिक रूप से, भारत में क्षेत्रीय दलों ने राज्य-स्तरीय पहचान, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और स्थानीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है, जो कि राष्ट्रीय दलों द्वारा ज़्यादातर अनदेखा किए गए हैं। २०१९ के चुनावों में, क्षेत्रीय दलों ने, या तो जानबूझकर राजनीतिक गठबंधनों में शामिल होकर या अपने दम पर चुनाव लड़कर, अपनी बढ़ती राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में उनका प्रभाव कभी अधिक स्पष्ट था, जहाँ उन्होंने राष्ट्रीय दलों के वर्चस्व को प्रभावी ढंग से चुनौती दी, क्षेत्रीय चिंताओं को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ले गए।

यह पत्र १७वें लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों द्वारा उनके चुनावी प्रदर्शन, रणनीतियों और गठबंधनों की खोज के माध्यम से निभाई गई बहुमुखी भूमिका का अध्ययन करना चाहता है। इसके अलावा, यह सवाल उठाएगा कि क्षेत्रीय दलों ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्थितियों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा। इस अध्ययन में क्षेत्रीय दलों की सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करके, हम भारतीय राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव और भारत में क्षेत्रवाद से प्रभावित संभावित संभावनाओं का पता लगाएंगे।

अध्ययन २०१९ के चुनावों में उनकी रणनीतियों, गठबंधनों और प्रदर्शनों के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), बीजू जनता दल (बीजेडी), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) जैसे चुनिंदा क्षेत्रीय खिलाड़ियों का मूल्यांकन करता है।

2. अनुसंधान का उद्देश्य:

1) १७वीं लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना।
2) क्षेत्रीय दलों द्वारा बनाए गए गठबंधनों की प्रकृति और चुनाव परिणामों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना।
3) राष्ट्रीय राजनीतिक आख्यान पर क्षेत्रीय दलों के प्रभाव का आकलन करना।
4) समकालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय दलों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझना।

3. साहित्य समीक्षा

भारत के १७वें लोकसभा चुनाव (२०१९) में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर साहित्य राष्ट्रीय राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। आहूजा (२०२०) राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को आकार देने में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती प्रासंगिकता पर जोर देते हैं, राज्य-विशिष्ट मुद्दों और क्षेत्रीय पहचानों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गुप्ता (२०१९) चुनावी परिणामों का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं, जिसमें कहा गया है कि टीएमसी, वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की और भाजपा के प्रभुत्व के बावजूद व्यापक राजनीतिक आख्यान में योगदान दिया। नायर (२०१८) एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि क्षेत्रीय दल किस तरह से गठबंधन की राजनीति में केंद्रीय बन गए हैं, खासकर २०१९ में। सूद (२०२१) गठबंधन शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का पता लगाते हैं, चुनावी समर्थन के बदले नीतिगत रियायतों की मांग करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। पटेल (२०१९) क्षेत्रीय दलों द्वारा बनाए गए रणनीतिक गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्षेत्रीय गठबंधनों के माध्यम से भाजपा के प्रभुत्व का मुकाबला करने में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। दास (२०२०) क्षेत्रीय दलों के दृष्टिकोण में रणनीतिक बदलावों पर चर्चा करते हैं, स्थानीय शासन और क्षेत्रीय पहचान पर उनके ध्यान को उजागर करते हैं ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो सके। कुमार (२०२१) गठबंधनों और चुनावी नतीजों की बदलती प्रकृति की जांच करते हैं, यह देखते हुए कि कैसे क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय चुनावों को आकार देने में तेजी से प्रभावशाली बन गए हैं। चंद्रा (२०२०) क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के प्रतिच्छेदन की खोज करते हैं, यह दिखाते हुए कि कैसे क्षेत्रीय दलों ने २०१९ के चुनावों के ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल को संभालने के लिए राज्य-स्तरीय मांगों को राष्ट्रीय चिंताओं के साथ संतुलित किया। साथ में, ये अध्ययन भारत के राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हैं, भविष्य के चुनावों को आकार देने में उनकी चुनौतियों और अवसरों दोनों को उजागर करते हैं।

4. शोध पद्धति

यह शोध पत्र मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करके २०१९ के भारतीय आम चुनाव पर क्षेत्रीय दलों के प्रभावों की पड़ताल करता है। अध्ययन के लिए ध्यान के कुछ मुख्य क्षेत्र चुनावी रणनीतियाँ, गठबंधन बनाने के पैटर्न, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में बहस के साथ उनका प्रतिच्छेदन हैं। प्राथमिक डेटा साक्षात्कार और सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया है, जबकि द्वितीयक डेटा चुनावी डेटा, साहित्य समीक्षा और मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से एकत्र किया गया है। क्षेत्रीय पार्टी की रणनीतियों, मतदाता चिंताओं और स्थानीय मुद्दों के प्रभावों की जांच करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी, विषयगत विश्लेषण और प्रवचन विश्लेषण का भी उपयोग किया गया है।

4.1. भारत के १७वें लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

भारत में १७वें लोकसभा चुनाव, राजनीतिक गठबंधन के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुए, इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों ने चुनावी नतीजों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गठबंधन की राजनीति में और राष्ट्रीय विमर्श के लिए चुनावी रणनीतियों और वैकल्पिक आख्यानों को संगठित करने में, क्षेत्रीय दलों ने इनसे आगे बढ़कर, कई राज्यों में इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी) और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) है।

क्षेत्रीय दलों ने चुनावी नतीजों को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई, आमतौर पर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग मामलों में राजनीतिक नतीजों को पलट दिया। वे गठबंधन के लिए सबसे उपयोगी थे, जबकि भाजपा और कांग्रेस को गठबंधन बनाने में अपने लाभ के लिए कुछ राज्यों को अपने पक्ष में करने में कठिनाई हो रही थी। भाजपा को विधिवत महागठबंधन चुनौती में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा शामिल थे।

२०१९ के चुनावों में, क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय मंच पर स्थानीय मुद्दों को जोरदार तरीके से पेश करके, राष्ट्रीय दलों के प्रति-आख्यान प्रस्तुत करके और क्षेत्रीय पहचान की प्रमुखता को उभारकर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय दलों के सामने आने वाली चुनौतियों में विखंडन, राष्ट्रीय दलों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा और गठबंधनों पर निर्भरता शामिल हैं। क्षेत्रीय दलों से भविष्य में इस अनूठी भारतीय राजनीति शैली में विखंडन की जकड़न को दूर करने की उम्मीद की जाती है, जो राष्ट्रीय दलों द्वारा लगाए गए सत्ता के केंद्रीकृत ढांचे को दृढ़ता से चुनौती देती है। इसका मतलब है कि भारत की चुनावी राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ रहा है, जहाँ स्थानीय समस्याएँ और राज्य-स्तरीय पहचान चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय आख्यानों जितनी ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं।

१७वें लोकसभा चुनाव २०१९ में क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) ने तमिलनाडु में २३ सीटें जीतीं, जिससे वे राज्य में प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गए और दक्षिण भारतीय राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ बन गई। एआईटीसी (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) ने पश्चिम बंगाल में २२ सीटें जीतीं, जिससे राज्य में भाजपा के विस्तार को चुनौती मिली और भाजपा के अभियान को कड़ी टक्कर मिली। बंगाल में एआईटीसी के इस प्रदर्शन से यह साबित होता है कि क्षेत्रीय दल न केवल अपनी राज्य सत्ता को बचा सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं।

वाईएसआरसीपी (वाईएसआर कांग्रेस पार्टी) ने आंध्र प्रदेश में २२ सीटें जीतीं, जो राज्य में मुख्य राजनीतिक दल के रूप में उभरी और राज्य के विकास तथा इसके संस्थापक वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की नीति पर जोर दिया। इस प्रदर्शन से यह साबित हुआ कि क्षेत्रीय दलों की अपने राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ है और उनका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में भी महसूस किया जाता है।

बिहार में जेडी(यू) (जनता दल (यूनाइटेड)) ने गठबंधन के तहत १६ सीटें जीतीं, जिससे यह साबित हुआ कि क्षेत्रीय दल मजबूत गठबंधन की राजनीति कर सकते हैं और सत्ता में भागीदार बन सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना (एसएस) ने १८ सीटें जीतीं और भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गई, लेकिन बाद में भाजपा से अलग हो गई और महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल हो गई।

ओडिशा में बीजद (बीजू जनता दल) ने १२ सीटें जीतीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी। इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि क्षेत्रीय दल अपने राज्य में राजनीतिक प्रभाव का विस्तार कर सकते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में योगदान दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में बीएसपी (बहुजन समाज पार्टी) ने १० सीटें जीतीं, राज्य की दलित और पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल करके अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया।

१७वीं लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का योगदान महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने अपने-अपने राज्यों में प्रगति की और राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावी ताकत के रूप में उभरे। उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति में उनका स्थान और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है तथा वे राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।

4.2. भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का ऐतिहासिक संदर्भ

स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों से ही क्षेत्रीय दलों ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय मुद्दों के आधार पर राष्ट्रीय दलों का विरोध किया। महाराष्ट्र में, शिवसेना महाराष्ट्रियों के अधिकारों को लेकर अधिक चिंतित थी और उसने राज्य में प्रवासियों की आमद का विरोध किया।

१९७० और १९८० के दशक में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद और अधिक क्षेत्रीय दल उभरे। जनता पार्टी ने १९७७ में दिखाया कि भारत में गठबंधन की राजनीति संभव है; इसने इंदिरा गांधी के शासन का विरोध करने वाले क्षेत्रीय और राष्ट्रीय तत्वों को एक साथ लाया। १९८९ के राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन में जिसने केंद्र में सरकार बनाई, क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय शासन में अपनी बात रखने के बारे में बहुत शोर मचाया।

१९९०-२००० से, क्षेत्रीय एकीकरण वास्तव में कठिन हो गया और क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय शासन में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनकर उभरे। संयुक्त मोर्चा (१९९६) कई क्षेत्रीय दलों (डीएमके, टीडीपी और वामपंथी दलों सहित) की भागीदारी से गठित एक गठबंधन सरकार थी। १९९० के दशक के उत्तरार्ध में भाजपा के उदय के साथ, क्षेत्रीय एकीकरण को बल मिला, जो अब एनडीए के साथ काम कर रहा है, जिसमें कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं।

२०१० के दशक में, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के उदय और उसके बाद भाजपा के सामान्यीकरण के साथ, क्षेत्रीय दलों का महत्व नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। क्षेत्रीय दलों के पास अभी भी राज्यों पर हावी होने, काफी सीटें जीतने और इस तरह राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रभाव था।

क्षेत्रीय दल रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय अधिकारों के स्थानीय मुद्दों पर जोर देते हुए राज्य की पहचान और स्वायत्तता के बारे में आक्रामक हो गए हैं। क्षेत्रवाद की बाढ़ ने राज्य-स्तरीय और राष्ट्रीय चुनावों में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बढ़ावा दिया है।

१७वीं लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन

क्षेत्रीय दल जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने के साथ-साथ अपने राज्यों में चुनाव परिणामों को आकार दिया है, वे अभी भी लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी), तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और आंध्र प्रदेश में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) जैसे विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने राज्य-स्तर और राष्ट्रीय-स्तर के परिणाम निर्धारित करने में इन दलों की शक्ति का प्रदर्शन किया है।

इन राज्यों में टीएमसी, बीजेडी, डीएमके और वाईएसआरसीपी की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से स्थानीय चिंताओं को ध्यान में रखकर और अपने लोगों के लिए क्षेत्रीय पहचान का प्रतिनिधित्व करने को दिया जाता है। यह स्पष्ट हो गया है कि यह पार्टी वास्तव में राज्यों में राजनीतिक कथानक को स्थापित करने में योगदान देती है और वास्तव में, गठबंधन व्यापार में बहुत अधिक योगदान देती है, या तो राष्ट्रीय छत्र के नीचे यात्रा करती है या राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करती है।

क्षेत्रीय पहचान की राजनीति कुछ हद तक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पार्टियाँ मतदाताओं को जोड़ने के लिए क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक गौरव और स्थानीय शासन का फायदा उठाती हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उनका प्रतिनिधित्व-चाहे संघीय अधिकार, भाषाई पहचान या राज्य स्वायत्तता के रूप में घोषित किया जाए-चुनावी जीत की दिशा में एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है।

राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व के बावजूद, क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण राज्यों में जीत हासिल करके भारत के बहुस्तरीय राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी निरंतर प्रासंगिकता साबित की है। स्थानीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, ये पार्टियाँ गठबंधन की राजनीति में भी महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, इस प्रकार भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने में अपरिहार्य बन गई हैं।

4.3. २०१९ के लोकसभा चुनावों में चुनावी गठबंधन और गठबंधन की राजनीति

२०१९ के लोकसभा चुनावों में भारत में क्षेत्रीय दलों के लिए गठबंधन की राजनीति और चुनावी गठबंधन की प्रमुख भूमिका रही। समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन ने राज्य में भाजपा को चुनौती देने की आकांक्षा की। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) स्वतंत्र रही, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में भाजपा के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए उसने क्षेत्रीय ताकतों के साथ गठबंधन किया।

२०१९ के लोकसभा चुनावों में चुनावी गठबंधन और गठबंधन की राजनीति से अब तक जनता में वृद्धि का विषयबनी हुई थी। क्षेत्रीय दलों ने इस कहानी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिखाया। "एम. के. स्टालिन की स्थिरता को देखते हुए, तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस गठबंधन बनाया गया ताकि उस राज्य में भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साझेदारी की जा सके," क्योंकि शुरुआत से ही अधिकांश गठबंधन किसी विचारधारा पर आधारित नहीं थे, बल्कि द्रविड़ राजनीति, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और तमिल पहचान की सुरक्षा पर आधारित थे। इसके अलावा, वे राष्ट्रीय स्तर पर होंगे ताकि क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रखा जा सके।

4.4. २०१९ के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय राजनीति पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल बहुत महत्वपूर्ण हैं और जहाँ तक गठबंधन की राजनीति का सवाल है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वे हमेशा राष्ट्रीय दलों के एजेंडे का मुकाबला करने के लिए लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय विमर्श को आगे बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। २०१९ के लोकसभा चुनावों में, यह साबित हो गया है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति को आकार दे सकते हैं और देते रहेंगे, भले ही केंद्र में भाजपा स्पष्ट रूप से बहुमत में थी।

नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्र शामिल हैं जहाँ क्षेत्रीय दलों ने अपनी छाप छोड़ी है, जैसे संघवाद और राज्य स्वायत्तता, संसाधन वितरण, भाषा नीतियाँ, या राष्ट्रीय दलों के वर्चस्व को चुनौती देना। इन राज्यों में तृणमूल कांग्रेस (TMC), YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) और DMK शामिल हैं, जिन्होंने राज्य स्वायत्तता और अधिक संतुलित संघीय ढांचे की माँग की और संघर्ष किया, साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच समान संसाधन वितरण की माँग की, स्थानीय विकास के लिए कुल राजस्व का अधिक हिस्सा रखने की माँग की।

क्षेत्रीय दलों ने भी कई ऐसे मुद्दों को सुलझाया है जिन्हें राष्ट्रीय दलों ने अकेला छोड़ दिया था। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण टीएमसी या डीएमके का है जो कभी-कभी पहचान की राजनीति का लाभ उठाते हैं, स्थानीय संस्कृति और पहचान के रक्षक के रूप में प्रचार करते हैं, और इसके अलावा राज्य के किसानों के आर्थिक कल्याण, सिंचाई योजनाओं और स्थानीय नियंत्रण के लिए राजस्व के अधिक आवंटित स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं।

ये न केवल नीति पर निर्णय होंगे, बल्कि क्षेत्र-आधारित दल राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, राज्य-विशिष्ट मुद्दों और क्षेत्रीय चिंताओं पर अधिक ध्यान देंगे जिन्हें राष्ट्रीय एजेंडे से अलग रखा जा सकता है। गठबंधनों के साथ या विपक्षी ताकतों के रूप में उनकी सह-उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर रखे जाएं।

क्षेत्रीय दलों ने नीतिगत निर्णय तैयार करके, राष्ट्रीय पार्टी के आधिपत्य का सामना करके और चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण, संघवाद, स्थानीयता और क्षेत्रीय पहचान पर राष्ट्रीय विमर्श को आकार देकर भारत में राजनीतिक परिदृश्य के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

4.5. २०१९ के लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों के सामने आने वाली चुनौतियाँ

इनमें सीमित राष्ट्रीय अपील, आंतरिक विखंडन, मजबूत राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा और अंत में, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय आख्यान में हेरफेर के मुद्दे शामिल हैं। क्षेत्रीय दल अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर अपील के बड़े केंद्रों में व्यवहार्य साबित हो सकने वाले मुद्दों के निर्माण की तुलना में राज्य-केंद्रित मुद्दों में अधिक व्यस्त हैं।

नेतृत्व संकट, वैचारिक विभाजन, गुटबाजी और दलबदल के रूप में आंतरिक विखंडन हो सकता है। विशेष रूप से भाजपा के साथ प्रतिस्पर्धा में, क्षेत्रीय दलों की आंतरिक ताकत कम होती जा रही है। राष्ट्रीय ताकत और अपील के साथ, ये दल क्षेत्रीय दलों के लिए प्रमुख प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, संसाधनों के माध्यम से खुले तौर पर सक्रिय होते हैं, भाजपा सक्रिय है। हाल ही में, आक्रामक रणनीतियों और पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत नेतृत्व द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपील करने के लिए किए गए अभियानों ने क्षेत्रीय दलों को उनके संतुलन से बाहर कर दिया है, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी हावी हो गए हैं जहाँ ये दल ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत थे।

संसाधन की कमी क्षेत्रीय दलों के लिए एक और बाधा साबित होती है। राष्ट्रीय होने की वजह से, आमतौर पर राष्ट्रीय दलों के पास कहीं ज़्यादा वित्तीय संसाधन, मीडिया पहुंच और संगठनात्मक बुनियादी ढांचा उपलब्ध होता है और इसलिए वे दूर-दराज के क्षेत्रों में अभियान प्रबंधन, मतदाता पहुंच और पार्टी मशीनरी के रखरखाव के लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों को आमतौर पर प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है। वास्तव में, राष्ट्रीय दल हर स्पष्ट राजनीतिक भाषण पर प्रभुत्व रखते हैं, राष्ट्रीय अर्थ के बड़े, पैनोरमा मुद्दों के पक्ष में क्षेत्रीय चिंता के क्षेत्रों को अनदेखा करते हैं।

भारत में क्षेत्रीय दलों को क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ने और दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

5. निष्कर्ष

राष्ट्रीय राजनीति में सफल भागीदारी के लिए जनता दल (सेक्युलर) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ना पड़ता है जो कभी-कभी राज्य या क्षेत्रीय सीमाओं से मेल खाती हैं, जैसा कि इन चुनावों ने दिखाया है। चुनावों में भाजपा की पूरी जीत हुई जबकि अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ - जैसे कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), बीजू जनता दल (बीजेडी), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) यह दिखाती हैं कि दिल्ली में बनाई गई नीतियों को उनके राज्यों में लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे राष्ट्रीय दलों की कुल शक्ति के खिलाफ अपने-अपने राज्यों में मजबूत जनादेश हासिल करने में कामयाब रहीं और क्षेत्रीय मुद्दे, पहचान, संघवाद एवं स्थानीय शासन को आवाज़ मिली। हालाँकि, उन्हें बाहरी खतरों का भी सामना करना पड़ता है जो उनके मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से परे क्षेत्रों में उनकी पहुँच को सीमित करते हैं जैसे कि नेतृत्व संकट, खराब संगठन और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा उन पर डाला जाने वाला दबाव। इस प्रकार, जबकि इस तरह की पहचान-आधारित लामबंदी एवं ध्रुवीकरण की राजनीति अवसर प्रदान करती है, वे क्षेत्रीय दलों के लिए जोखिम भी पैदा करती हैं जिन्हें स्थानीय मांगों को राष्ट्रीय राजनीतिक आख्यानों के साथ जोड़ना पड़ता है। अंत में, क्षेत्रीय दलों का भाग्य पूरी तरह से बदलते राजनीतिक चरों के प्रति उनकी अनुकूलन क्षमता, आंतरिक एकता के भीतर जटिलताओं के इर्द-गिर्द उनके संचालन, राष्ट्रीय दलों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने और अधिक व्यापक, समावेशी राजनीतिक एजेंडा स्थापित करने में निहित होगा। उभरते राजनीतिक माहौल में निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों को गठबंधन निर्माण एवं भारतीय लोकतंत्र के भविष्य में और भी बड़ी भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा।

संदर्भ:

Bhambhri, C. P. (2005). Indian politics: 2001-2004 political process and change of government. Shipra.
Chahar, S. S. (2004). Dynamics of electoral politics in Haryana (Vol. 1). Sanjay.
Chaudhary, A. K. (2019, May 28). 17वीं लोकसभा के सबसे यंग और सबसे बूढ़े सांसद को जानिए [Know about the youngest and oldest MPs in the 17th Lok Sabha]. One India. Retrieved from https://www.oneindia.com
Deccan Herald. (2019, April 7). Congress launches 'Ab Hoga Nyay' for Lok Sabha polls. Deccan Herald. Retrieved from https://www.deccanherald.com
DeSouza, P. R., & Sridharan, E. (Eds.). (2006). India's political parties: Readings in Indian government and politics (6th ed.). Sage Publications.
Dutt, R. C. (1992). People and politics: The Indian experience. Lancer Publishers Pvt. Ltd.
ET Bureau. (2019, April 17). Temple visit was part of Rahul Gandhi's last leg of campaign in Wayanad on Wednesday. ET Bureau. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com
HT. (2019, May 23). Lok Sabha election results 2019: GST, demonetisation had no impact on the ground. HT. Retrieved from https://www.hindustantimes.com
Indian Election Commission. (2009). Results of Indian general elections 2009. Retrieved from https://results.eci.gov.in
Kashyap, S. C. (2010). Our constitution: An introduction to India's constitution and constitutional law. National Book Trust.
Kaushik, S. (1982). Elections in India: Its social basis. K.P. Bagchi & Company.
Outlook Web Bureau. (2017, November 30). Rahul Gandhi is Janeu-Dhari Hindu, says Congress. Outlook. Retrieved from https://www.outlookindia.com
Press Trust of India. (2019, May 5). Modi government left economy in "dire straits", says Manmohan Singh. News18. Retrieved from https://www.news18.com
Roy, R., & Sisson, R. (Eds.). (1990). Diversity and dominance in Indian polities. Sage Publications.
Weiner, M. (1967). Party building in a new nation: The Indian National Congress. The University of Chicago Press.